छत्तीसगढ़
सहकारी समाचार
सहकारिता की उपलब्धियों पर विशेषांक

वर्ष- 23 | जून 2026 विशेषांक | RNI NO. CHHHIN/2012/45105 | पृष्ठ-12 | मूल्य 500/- वार्षिक

पीएम मोदी ने किया जीविका निधि साख सहकारी संघ का शुभारम्भ

अब महिलाओं को बैंकों या संस्थानों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी : पीएम मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य बिहार की ग्रामीण महिलाओं, विशेषकर जीविका से जुड़ी दीदियों को कम ब्याज दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी तरह डिजिटल इस व्यवस्था से महिलाओं को बैंकों या संस्थानों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि उन्हें सीधे मोबाइल फेन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए वित्तीय सहयोग मिल सकेगा। उन्होंने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया और बिहार की माताओं-बहनों को शुभकामनाएँ दीं।

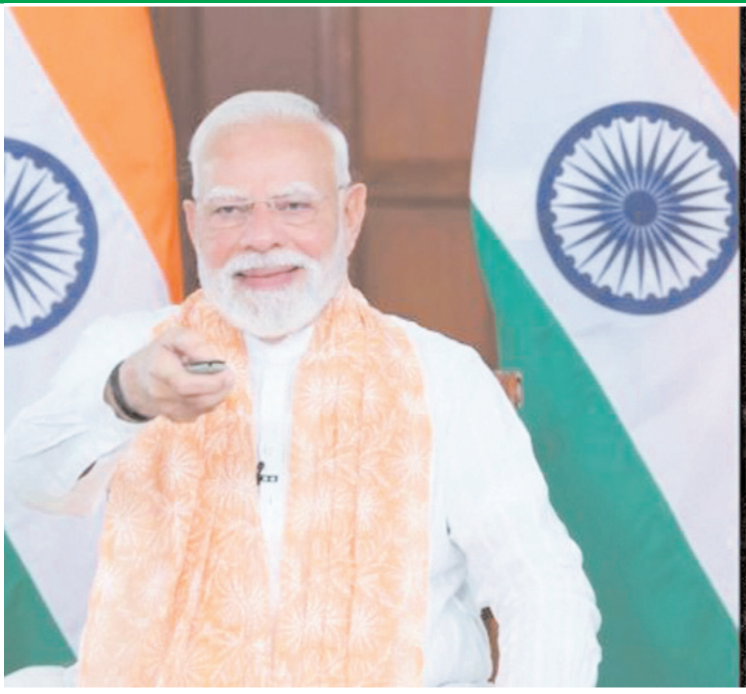

पीएम ने गिनाई केंद्र सरकार की योजनाएं

अपने संबोधन में मोदी ने महिला सशक्तिकरण से जुड़ी केंद्र सरकार की योजनाओं का भी उल्लेख किया, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर जल, आयुष्मान भारत, मुफ्त राशन योजना, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी और बैंक सखी जैसी पहलें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये योजनाएँ महिलाओं के जीवन को आसान बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए समर्पित हैं। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों द्वारा उनकी दिवंगत माताजी पर की गई टिप्पणी को लेकर गहरी पीड़ा भी व्यक्त की और कहा कि, यह अपमान केवल उनकी मां का नहीं, बल्कि देश की सभी माताओं और बेटियों का अपमान है। उन्होंने बिहार की महिलाओं से आग्रह किया कि वे ऐसी मानसिकता को अस्वीकार करें।

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ को मिला नया नेतृत्व
सौरभ शर्मा ने संभाला प्राधिकृत अधिकारी का पदभार

25 वर्षों का व्यापक अनुभव और शैक्षणिक योग्यता

नवनियुक्त प्राधिकृत अधिकारी सौरभ शर्मा सहकारिता, पत्रकारिता, सामाजिक नेतृत्व एवं डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में 25 वर्षों से अधिक का लंबा और व्यापक अनुभव रखते हैं। शैक्षणिक रूप से वे एम.ए. (इतिहास), एल.एल.बी. तथा एम.जे.एम.सी. की उच्च डिग्रियों से संपन्न हैं। वर्तमान में वे 'सहकार भारती, छत्तीसगढ़' में प्रदेश कार्यालय मंत्री के दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। वे सहकारिता जागरण, संगठन विस्तार और ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण के कार्यों में लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

रायपुर। आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ ने आदेश जारी करते हुए श्री सौरभ शर्मा को आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के बोर्ड की शक्तियों के प्रयोग हेतु प्राधिकृत किया है। विभाग द्वारा यह निर्णय छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49(8) तथा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी नियम 1962 के प्रावधानों के तहत गठित छानबीन समिति की अनुशंसा पर लिया गया है।

बुधवार को श्री सौरभ शर्मा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ सदस्य और सहकार भारती के प्रदेश महासचिव श्री कनीराम की मौजूदगी में पद का विधिवत् कार्यभार ग्रहण किया।

आधुनिक तकनीक और सामाजिक विकास में उल्लेखनीय योगदान

श्री शर्मा को पत्रकारिता, जनसंपर्क, सहकारी संस्थाओं के गठन, किसान उत्पादक संगठनों (FPO), महिला सहकारिता तथा डिजिटल मीडिया प्रबंधन के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए जाना जाता है। वे आधुनिक तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) एवं डिजिटल माध्यमों के उपयोग द्वारा जनजागरण और संगठन निर्माण के अभिनव मॉडल विकसित करने में माहिर हैं। इसके अलावा, उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में सामाजिक समरसता, ग्राम विकास, किसान उत्थान, महिला सशक्तिकरण, जनजातीय विकास तथा युवा नेतृत्व निर्माण के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं।

सहकारी आंदोलन को मिलेगी नई दिशा

सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण का सशक्त माध्यम मानने वाले श्री सौरभ शर्मा लंबे समय से समाज एवं संगठन के बीच एक मजबूत सेतु की भूमिका निभा रहे हैं। सहकारिता विभाग के इस निर्णय से प्रदेश में सहकारी आंदोलन को एक नई दिशा और गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस अवसर पर संघ की प्रबंध संचालक श्रीमती पूर्णिमा सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी पीसी ध्रुव एवं संघ कर्मचारीगण उपस्थित रहे। श्री शर्मा को यह नई और बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर सहकारिता क्षेत्र से जुड़े विभिन्न संगठनों, कार्यकर्ताओं एवं सामाजिक प्रतिनिधियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें अपनी शुभकामनाएं और बधाई दी है।

रमेश कुमार शर्मा बने सहकारिता आयुक्त

रायपुर। राज्य शासन ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए आईएएस अधिकारी रमेश कुमार शर्मा, भा.प्र.से. 2010 बैच को नई जिमेदारी सौंपी है। शर्मा जो वर्तमान में सचिव, गृह विभाग के पद पर पदस्थ हैं, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छीसगढ़ के पद पर पदस्थ किया गया है।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन बनी समस्याओं के समाधान का भरोसेमंद माध्यम

कोरबा। शासन की जनहितकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ आमजनों तक समय पर पहुंचाने तथा उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सशक्त माध्यम बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों और मांगों पर जिला प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जा रहा है। कोरबा जिले में अब तक 'राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन, खाद्य, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास सहित विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 505 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 142 से अधिक आवेदनों का सफलतापूर्वक निराकरण कर संबंधित आवेदकों को राहत पहुंचाई गई है। शेष प्रकरणों पर भी विभागीय स्तर पर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

पहली बार इफको की 55वीं आमसभा में महिला नेतृत्व का सम्मान

नई दिल्ली। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) की 55वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) सोमवार को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित हुई, जिसमें महिला सशक्तिकरण, सहकारिता आंदोलन और सतत कृषि को केंद्र में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। कार्यक्रम में देशभर से 850 से अधिक सहकारी नेता, सदस्य समितियों के प्रतिनिधि, किसान और अन्य हितधारक शामिल हुए।

शकीला अख्तर को 'इफको सहकारिता रत्न पुरस्कार'

भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड के अध्यक्ष दिलीप संघाणी ने कहा कि, इफ्को भारतीय सहकारिता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि, वर्ष 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किए जाने के संदर्भ में महिलाओं को सहकारिता से जोडना और भी महत्वपूर्ण हो गया है। इस अवसर पर पहली बार इफ्को सहकारिता रत्न और सहकारिता बंधु पुरस्कार महिला हस्तियों को प्रदान किए गए। जम्मू-कश्मीर की शकीला अख्तर को वर्ष 2024-25 का "इफ्को सहकारिता रत्न पुरस्कार" 11 लाख रुपये की सम्मान राशि के साथ प्रदान किया गया। उन्हें महिला कृषि और सहकारिता आंदोलन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

नैनो उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर

एजीएम में नैनो उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने, छोटे एवं सीमांत किसानों को मजबूत करने और टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम में भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड, इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस, कॉर्डेट, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी विकास न्यास, इफ्को बाजार, इफ्को-एमसी और किसान रुरल फाइनेंस समेत विभिन्न पहलों और निवेशों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम ने "विकसित भारत" के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप आत्मनिर्भर और समृद्ध ग्रामीण भारत के निर्माण में सहकारिता क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को फिर से रेखांकित किया।

इफ्को ने 4,585 करोड़ रुपये का लाभ कमाया

इफ्को के प्रबंध निदेशक के. जे. पटेल ने बताया कि, संस्था ने वर्ष 2024-25 में 4,585 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है। उन्होंने कर्मचारियों के लिए 490.65 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन की घोषणा की, जिसे अब तक का सबसे बड़ा प्रोत्साहन बताया गया। वही निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेतन 20,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है जिसके लिए अतिरिक्त 140 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

भावना गौंडलिया को मिला इफको सहकारिता बंधु पुरस्कार

इसके अलावा गुजरात की भावना गौंडलिया को वर्ष 2024-25 का ÷इफ्को सहकारिता बंधु पुरस्कार÷ 11 लाख रुपये की नकद राशि के साथ प्रदान किया गया। उन्हें कृषि क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण और सहकारिता आंदोलन में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। सभा को संबोधित करते हुए दिलीप संघाणी ने कहा कि सहकारी समितियों, किसानों और पेशेवर कर्मचारियों के सहयोग ने इफ्को को विश्व की अग्रणी सहकारी संस्थाओं में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि इफ्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि÷ पिजन का वास्तविक उदाहरण है।

छत्तीसगढ़ में 300 बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी व मत्स्य सहकारी समितियों का शुभारम्भ

सुशासन दिवस पर जगदलपुर में सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने समितियों को प्रदान किया पंजीयन प्रमाण पत्र

जगदलपुर। केन्द्र सरकार की सहकार से समृद्धि अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन को मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सहकारी समितियों में नई सुविधाएं बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए डेयरी, मत्स्य पालन के क्षेत्र में नई सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

वन एवं सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप ने 25 दिसम्बर को जगदलपुर में राज्य में गठित 300 से अधिक नवगठित बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी व मत्स्य सहकारी समितियों का शुभारम्भ किया। गौरतलब है कि भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में देशभर के नवगठित 10 हजार से अधिक बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी एवं मत्स्य समितियों के शुभारंभ अवसर पर वन एवं सहकारिता मंत्री वर्चुअल रूप से जुड़े।

500 नये बहुउद्देशीय पैक्स गठन प्रक्रियाधीन

वन एवं सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप ने कार्यक्रम में सुशासन दिवस पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करते हुए कहा कि, अभी प्रदेश में कार्यरत 2058 पैक्स तथा लैम्प्स द्वारा प्रदेश के कृषकों को कृषि ऋण तथा खाद-बीज एवं विभिन्न तरह की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इन्हें और अधिक सक्षम बनाया जा रहा है। राज्य में 500 नये बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

57 नई दुग्ध समितियों का पंजीयन

उन्होंने कहा कि, राज्य में दुग्ध उत्पादक कृषकों की आय में वृद्धि के लिए एनडीडीबी के साथ राज्य दुग्ध संघ तथा राज्य सरकार के साथ त्रिपक्षीय एमओयू किया गया है। राज्य में 57 से अधिक नवीन दुग्ध समितियों का पंजीयन कर लिया गया है। राज्य के 113 वन-धन समितियों को भी प्राथमिक बहुउद्देशीय लघु वनोपज सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत किया गया है। 169 नवीन मत्स्य समितियों का गठन किया गया है।

725 नए गोदाम बनाए जा रहे

सहकारिता मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि, पिछले एक वर्ष में सहकारी बैंकों की 16 नवीन शाखाएं प्रारंभ किए गए हैं। पैक्स समितियों में 2058 माईक्रो एटीएम उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश के 2014 पैक्स समितियों को कॉमन सर्विस सेन्टर की सुविधा, 25 पैक्स समितियों में प्रधानमंत्री जनऔषधि केन्द्र प्रारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक तथा 6 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में 300 से अधिक पदों पर भर्ती की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है और अभ्यर्थियों को नियक्ति पत्र प्रदान किया गया है। राज्य के 2058 पैक्स में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र स्थापित किया गया है, पूर्ण रूप से विकसित होने के उपरान्त इन केन्द्रों में कृषकों को मिटटी परीक्षण, मौसम पूर्वानुमान तथा कृषि तकनीक संबंधी जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। वहीं अन्न भण्डारण योजनांतर्गत 200 मेट्रिक टन क्षमता के 725 नवीन गोदामों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से 625 गोदामों का निर्माण पूर्ण हो चुके हैं।

इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष मनीराम कश्यप, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, पूर्व विधायक द्वय बैदूराम कश्यप एवं लच्छूराम कश्यप सहित अन्य जनप्रतिनिधि और कलेक्टर एवं प्राधिकृत अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक हरिस एस तथा प्रबंध संचालक एवं संयुक्त अपेक्स बैंक केएन कांडे, अपेक्स बैंक महाप्रबंधक युगल किशोर एवं बड़ी संख्या में सहकारी समितियों के पदाधिकारियों के अलावा सहकारी समितियों से जुड़े कृषक एवं नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन छग राज्य सहकारी संघ के प्रशिक्षक विवेक पांडे ने किया।

ये कार्यक्रम भी संपन्न हुए

कार्यक्रम को सांसद बस्तर श्री महेश कश्यप ने भी सम्बोधित किया। इस मौके पर बस्तर अंचल के 10 नवीन सहकारी समितियों को पंजीयन प्रमाण पत्र, 25 किसानों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड तथा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति बड़े कापसी को माइक्रो एटीएम प्रदान किया गया। साथ ही प्रदेश के पहले ई-पैक्स समिति ओरछा सहित माइक्रो एटीएम से सर्वाधिक ट्रांजेक्शन करने वाले सहकारी समितियों मद्देढ़, केशरपाल एवं नारायणपुर सहित लोक सेवा केन्द्र के बेहतर संचालन के लिए पैक्स समितियों माढ़पाल, कांकेर, केरलापाल एवं बांसकोट को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री से मिले कश्यप : सहकारिता क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों और मांगों को लेकर की चर्चा

सहकार से समृद्धि प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को लेकर मंत्री केदार कश्यप की पहल, विभिन्न मांगों और लक्ष्यों पर बातचीत

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने मंगलवार 25 मार्च को दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल से सौजन्य भेंट की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय राज्यमंत्री श्री मोहोल को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के विजन को लेकर किये जा रहे कार्यों और उपलब्धियों से अवगत कराया।

सहकारिता मंत्रालय से विभिन्न मांगों को लेकर कश्यप की पहल

मंत्री केदार कश्यप ने राज्य सरकार की मांगों से केंद्रीय राज्यमंत्री मोहोल को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि, सहकार से समृद्धि की दिशा में छत्तीसगढ़ प्रदेश उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। जिसे गति प्रदान करने के लिये पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजनांतर्गत प्रथम चरण में 2028 पैक्स का चयन किया गया है। शेष 30 पैक्स तथा सहकार से समृद्धि अंतर्गत प्रस्तावित 500 नवीन पैक्स के लिए सहमति शीघ्र दिया जाए।

अन्य प्रमुख मांगें

नाबार्ड के प्रशिक्षण संस्थान 'बर्ड' की स्थापना छत्तीसगढ़ में भी किया जाये, जिससे राज्य के पैक्स/DCCB तथा अपेक्स बैंक के अधिकारी/ कर्मचारियों एवं संचालक मण्डल सदस्यों एवं पदाधिकारियों का प्रशिक्षण की राज्य स्तरीय व्यवस्था किया जा सके। राज्य मे सहकारी बैंक द्वारा अल्पकालीन कृषि ऋणों के लिए वर्ष 2024-25 मे राशि रू 8500 करोड़ का ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरुद्ध आज दिनांक तक राशि रू 7709 करोड़ का ऋण वितरण किया जा चुका है। "नाबार्ड की अल्पकालीन कृषि ऋण हेतु रियायती ब्याज पर पुनरवृत योजना" (Concessional Refinance) अंतर्गत वितरित ऋण का 45% तक अल्प ब्याज दर पर पुनर्वित्त सहकारी बैंकों को उपलब्ध कराया जाना होता है, किन्तु प्रत्येक वर्ष नाबार्ड द्वारा 10-20% तक ही राशि उपलब्ध करायी जाती है। इस वर्ष केवल राशि रू. 1150 करोड़ ही उपलब्ध कराया गया है, जो कि कुल ऋण वितरण का 14.9% ही है। अतः पॉलिसी अनुसार पूरी राशि उपलब्ध कराया जाए।

जनऔषधि केंद्र में सहित अनेक क्षेत्रों में पैक्स कि उपयोगिता में वृद्धि

सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने केंद्रीय राज्यमंत्री को जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के 28 पैक्स में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केन्द्र स्थापित हैं, जिनमें से 25 की स्थापना माननीय मंत्री जी की समीक्षा बैठक के उपरान्त की गई है और राज्य में 2029 पैक्स में कॉमन सर्विस सेन्टर की स्थापना की गई है, जिनमें से 1103 की स्थापना माननीय मंत्री जी की समीक्षा बैठक के उपरान्त की गई है। इन पैक्स द्वारा अब तक रू2.37 करोड़ का ट्रान्जेक्शन किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी 2058 पैक्स द्वारा भारतीय बीज सहकारी समिति में सदस्यता हेतु आवेदन पूर्ण कर लिया गया है, जिनमें से 1792 आवेदन माननीय मंत्री जी की समीक्षा बैठक के उपरान्त किये गये हैं।

प्रदेश के गन्ना विक्रेता कृषकों को भुगतान त्वरित रूप से करने की आवश्यकता होती है, उक्त बाबत् भारत सरकार द्वारा जारी मासिक कोटे में छूट देते हुए अधिक शक्कर बेचने की अनुमति प्रदान की जाए।

प्रदेश के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना पंडरिया के निर्माण हेतु NCDC से प्रदाय टर्म लोन की दिनांक 17/03/2025 की स्थिति में बकाया राशि 17.21 करोड़ (मूलधन 15.75 करोड़, सामान्य ब्याज 61.02 लाख एवं विलंबित अवधि के लिए ब्याज 84.79 लाख) हो गयी है। कारखाना द्वारा अब तक कुल राशि 137.84 करोड़ (मूलधन 81 करोड़ एवं ब्याज 56.84 करोड़) का भुगतान किया जा चुका है। कारखाने की कमजोर आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त ऋण पर विलंबित अवधि के लिए अधिरोपित ब्याज की राशि 84.79 लाख को माफ किए जाने का अनुरोध है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 अंतर्गत आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के लिए एक्सपोजर विजिट में छत्तीसगढ़ राज्य को भी शामिल किया जाए।

मंत्री केदार कश्यप ने केंद्रीय राज्यमंत्री को बताया कि माननीय केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी द्वारा दिनांक 25/08/2024 की समीक्षा उपरान्त सहकारिता विभाग ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उस पर विष्णुदेव साय सरकार ने पहल करते हुए एक संतोषजनक परिणाम को प्राप्त किया है।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में बहुउद्देशीय समितियों के गठन के लक्ष्य के विरूध्द 232 दुग्ध, 257 मत्स्य तथा 152 लघु वनोपज सहकारी समितियां, इस प्रकार कुल 641 नवीन समितियों का गठन कर लिया गया है, जिनमें से 512 समितियों का गठन माननीय मंत्री जी की समीक्षा बैठक के उपरान्त किया गया है। वहीं राज्य में कार्यरत 2058 पैक्स का पुनर्गठन कर 532 नवीन पैक्स के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

केदार कश्यप ने कहा कि राज्य के सभी 2058 पैक्स में भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय द्वारा जारी मॉडल बॉयलाज का अंगीकरण कर लिया गया है। माननीय मंत्री की उपस्थिति में 16 दिसंबर 2024 को राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ और एन.डी.डी.बी. के मध्य एम.ओ.यू. हस्ताक्षर किया गया। दुग्ध महासंघ के प्रबंधन और संचालन का हस्तांतरण भी 17 जनवरी 2025 को एन.डी.डी.बी. को कर दिया गया है।

भारतीय बीज सहकारी समिति को बीज विक्रय लाइसेन्स जारी

मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि, छत्तीसगढ़ राज्य बीज निगम द्वारा भारतीय बीज सहकारी समिति को बीज विक्रय लाइसेन्स जारी कर दिया गया है और बीज आपूर्तिकर्ताओं में नाम जोडने् की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। राज्य के सभी 2058 पैक्स द्वारा राष्ट्रीय सहकारी निर्यात समिति में सदस्यता हेतु आवेदन पूर्ण कर लिया गया है, जिनमें से 1924 आवेदन माननीय मंत्री जी की समीक्षा बैठक के उपरान्त किये गये हैं। इसी तरह राज्य के सभी 2058 पैक्स द्वारा राष्ट्रीय जैविक सहकारी समिति में सदस्यता हेतु आवेदन पूर्ण कर लिया गया है, जिनमें से 1915 आवेदन माननीय मंत्री जी की समीक्षा बैठक के उपरान्त किये गये हैं।

सहकारिता के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा

मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि, छत्तीसगढ़ कृषि सम्पन्न प्रदेश है जहाँ जैविक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा विपणन की व्यवस्था हेतु राष्ट्रीय जैविक सहकारी समिति छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी लघु वनोपज संघ के मध्य एमओयू निष्पादित किया गया है। संघ द्वारा जैविक समिति को 500 किलोग्राम आर्गेनिक शहद की आपूर्ति प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि माननीय अमित शाह जी की समीक्षा बैठक के उपरान्त राज्य में इमली, आटी, इमली फूल, चिरौंजी, गुठली, काजू, कालमेघ, हर्रा, कचरिया, गिलोय, महुआ फूल सूखा, शहद, आंवला सूखा, महुआ बीज, हर्रा साबुत, बहेड़ा साबूत, भेलवा, इमली बीज, चरोटा बीज, बहेड़ा कचरिया, आमचूर, मालकांगनी, करंज बीज, बेल, जामुन आदि 22 लघु वनोपजों का आर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्राप्त किया जा चुका है।

केंद्रीय सहकारिता अमित शाह की समीक्षा बैठक के उपरान्त सभी पैक्स में माईक्रो ए.टी.एम. उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य रहा है। धान उपार्जन के दौरान 03 माह की अवधि में माईक्रो ए.टी.एम. के माध्यम से राशि रू 116 करोड़ का ट्रांजेक्शन किया गया है। राज्य के 33 ग्राम पंचायतों में पैक्स द्वारा ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना का संचालन पॉयलेट के तौर पर प्रारंभ किया गया है। राज्य के चयनित सभी 2028 पैक्स गो-लाईव हो गये हैं। सभी पैक्स को अप्रैल 2025 तक ई-पैक्स करने का लक्ष्य है। विगत 06 माह में राज्य में 2.50 लाख कृषकों को रूपे केसीसी कार्ड वितरण किया गया है। राज्य के सभी पैक्स में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र स्थापित है। वर्ष 2024-25 में इन केन्द्रों के द्वारा अब तक राशि रू 1760.34 करोड़ से अधिक का ट्रांजेक्शन कर लिया गया है।

किसानों को 5 लाख तक ब्याज रहित ऋण

प्रदेश में पैक्स द्वारा सदस्य कृषकों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर 05 लाख की सीमा तक अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2024-25 में अब तक 15.21 लाख कृषक सदस्यों को राशि रू.7709 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है। प्रदेश में पैक्स द्वारा समर्थन मूल्य पर कृषकों से धान उपार्जन का कार्य किया जाता है। खरीफवर्ष 2024-25 में 25.49 लाख कृषकों से 149.25 लाख मिट्रिक टन धान का उपार्जन कर राशि रू 46,251.77 करोड़ का भुगतान किया गया है।

सहकारिता से जनजाति क्षेत्रों में आर्थिक विकास, रोजगार के अनेक कार्यक्रम

मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार द्वारा प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के आर्थिक उन्नयन तथा उन्हें दुग्ध सहकारिता से जोडने् के लिए प्रथम चरण में प्रदेश के 06 जिलों के 325 परिवारों को 650 दुधारू पशु प्रदाय करने की योजना एनडीडीबी द्वारा तैयार की गई है। इसके साथ ही सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अनाज भण्डारण योजना में आरआईडीएफ अंतर्गत राज्य में निर्माणाधीन 725 गोदामों को शामिल किया गया है। इनमें 665 गोदाम पूर्ण हो चुके हैं, शेष 60 गोदाम का निर्माण शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा।

अन्य उपलब्धियां

- एन.सी.सी.एफ के पोर्टल में सभी पैक्स का पंजीयन कराने में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य रहा है।
- माननीय मंत्री जी समीक्षा बैठक के उपरान्त राज्य में 1400 से अधिक सहकारी समितियों के खाते सहकारी बैंकों में खोले गये हैं।

साहू और शर्मा भी रहे मौजूद

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव, सहकारिता छत्तीसगढ़ शासन सुब्रत साहू, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ कुलदीप शर्मा मौजूद रहे।

'सहकार से समृद्धि' थीम पर लगी प्रदर्शनी से लोगों को मिली उपयोगी जानकारी

रायपुर। छततीसगढ़ के तीन दिवसीय राज्योत्सव में सहकारिता विभाग के स्टॉल में लोगों को बड़ी महत्त्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी मिली। सहकारिता विभाग द्वारा राज्योत्सव के अवसर पर ''सहकार से समृद्धि'' थीम पर प्रदर्शनी लगाई गई थी। ''सहकार से समृद्धि'' संकल्पना अंतर्गत 54 पहल प्रारंभ किये गये हैं, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में बहुद्देशीय एवं बहुआयामी पैक्स/ लघु वनोपज/मत्स्य/दुग्ध सहकारी सोसाइटियों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मॉडल बायलाज के अंगीकरण उपरांत पैक्स बहुद्देशीय पैक्स के रूप में परिवर्तित होकर अनेक तरह की नागरिक सेवाएं ग्रामीणों को उपलब्ध करा रही है, जिसमें प्रमुख सेवाओं जैसे धान खरीदी, खाद बीज वितरण, ऋण वितरण, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र, माइक्रो ए.टी.एम. से भुगतान, पैक्स को कामन सर्विस सेंटर के रूप में स्थापित करना, विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अन्न भंडारण योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र, एल पी जी वितरण और इथेनॉल संयंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। ''सहकार से समृद्धि'' थीम पर अलग-अलग माडल भी तैयार किया गया था।

छत्तीसगढ़ में 532 नए पैक्स गठन के लिए अधिसूचना जारी

कृषि ऋण के साथ खाद-बीज, माइक्रो-एटीएम से पैसे निकालने की मिलेगी सुविधा

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की संकल्पना 'सहकार से समृद्धि' को साकार करने में छत्तीसगढ़ अब अग्रणी राज्यों में है। इस दिशा में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की मंशानुरूप छत्तीसगढ़ में नवीन बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी तथा मत्स्य समितियों के गठन की कार्ययोजना बनाई गई, जिसे कार्यरूप में परिणित करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के दिशा-निर्देश पर राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में 532 नवीन पैक्स सोसाइटी के गठन की अधिसूचना 4 अप्रैल 2025 को जारी कर दी गई है।

सहकारिता विभाग के आयुक्त कुलदीप शर्मा ने बताया कि, केन्द्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह के दिशा-निर्देश व मुख्यमंत्री विष्णु देव साय तथा सहकारिता मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन से 532 पैक्स का गठन किया गया है। उल्लेखनीय है कि, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा रायपुर में 'सहकार से समृद्धि' विषय पर ली गई पहली बैठक 25 अगस्त 2024 में छत्तीसगढ़ में पैक्स की संख्या बढ़ाने और पैक्स की पहुँच गाँव-गाँव तक ले जाने की मंशा को इस निर्णय के साथ पूरा किया जा रहा है।

माइक्रो-एटीएम से पैसे निकालने की मिलेगी सुविधा

राज्य के विभिन्न गांवों में 532 नवीन सहकारी समितियों के गठन से अब किसानों को अपने गांव में ही किसानों को कृषि ऋण के साथ खाद-बीज लेने, माइक्रो-एटीएम से राशि आहरण की सुविधा मिलेगी। इस नवीन पैक्स में कामन सर्विस सेंटर, जनऔषधि केंद्र तथा किसान समृद्धि केंद्र का संचालन किया जाएगा। इससे प्रदेश के किसानों को उनके ग्राम में ही आवश्यक सभी सुविधाएं प्राप्त हो सकेगी।

'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक : केदार कश्यप

अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर आयोजित संगोष्ठी में शामिल हुए सहकारिता मंत्री केदार कश्यप

- **गौपालक किसानों, मत्स्य सहकारी किसानों को रुपे केसीसी कार्ड और डेयरी सोसायटियों को माइक्रो एटीएम बांटा**

रायपुर। सहकारिता एवं जल संसाधन मंत्री श्री केदार कश्यप 5 जुलाई को नवा रायपुर, अटल नगर में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) परिसर में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी में शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। उन्होंने इस दौरान गौपालक और मत्स्य पालक किसानों को रुपे केसीसी कार्ड और दुग्ध सहकारी समितियो को माइक्रो एटीएम वितरण किया।

मंत्री श्री कश्यप ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि, "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है, और माँ के प्रति हमारी श्रद्धा। उन्होंने कहा कि, यह अभियान प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक अनूठा तरीका भी है। माँ और प्रकृति दोनों ही जीवनदायिनी हैं, पोषण करती हैं, और बिना किसी स्वार्थ के अपनापन देती हैं। मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि, माँ के नाम पर एक पेड़ लगाना माँ के प्रेम को प्रकृति के साथ जोड़ता है। यह एक जीवंत श्रद्धांजलि है, जो न केवल माँ के प्रति हमारी भावनाओं को व्यक्त करती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक उपहार है।

पैक्स सोसायटियों को मजबूत किया जाए : केदार गुप्ता

अपेक्स बैंक के प्राधिकृत अधिकारी श्री केदार नाथ गुप्ता ने कहा कि अभियान का संदेश है - "माँ के लिए एक पेड़, धरती के लिए एक कदम" । सभी सहकारी समितियों के साथ इस नेक कार्य में हिस्सा लेने और अपनी माँ के प्रेम को प्रकृति के साथ जोड़ने का आह्वान किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि, केंद्र व राज्य सरकार की मंशा है कि पैक्स सोसायटियों को मजबूत किया जाए।

सामाजिक दायित्व निभाना भी जरूरी : कश्यप

उन्होंने कहा कि यह अभियान, "सहकारिता" के साथ, भारत में सामाजिक और पर्यावरणीय उत्थान के लिए महत्वपूर्ण पहलें हैं। ये सामूहिक भागीदारी और सामूहिक जिम्मेदारी पर आधारित हैं, और इनकी मूल भावना सहयोग, संरक्षण और समाज में योगदान देने की है। "एक पेड़ माँ के नाम" पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर की गई थी। इसका उद्देश्य माताओं की स्मृति में पेड़ लगाने को प्रोत्साहित करना और पर्यावरण संहिता को बढ़ावा देना है। यह अभियान प्रकृति और मातृत्व के बीच समानता को रेखांकित करता है, क्योंकि दोनों ही जीवन का पोषण करते हैं।

इनकी भी रही मौजूदगी

संगोष्ठी में छत्तीसगढ़ सहकारिता प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्री शशिकांत द्विवेदी, सहकारिता विभाग के सचिव डॉ सी आर प्रसन्ना, आयुक्त सहकारिता श्री कुलदीप शर्मा, एमडी अपेक्स बैंक श्री के एन कांडे, अपर आयुक्त श्री एच के दोषी, सहकारिता विभाग के अधिकारी सहित जिला सहकारी बैंको, मार्कफेड, लघुवनोपज, तथा एनसीडीसी तथा बड़ी संख्या में अपेक्स बैंक, जिला सहकारी बैंकों, जिला सहकारी संघ के अधिकारी गण मौजूद थे।

सहकारिता पर सरकार का सकारात्मक दृष्टिकोण : सुब्रत साहू

अपर मुख्य सचिव, सहकारिता, छत्तीसगढ़ शासन श्री सुब्रत साहू ने राज्य स्तरीय सहकारी संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में "सहकार से संमृद्धि" अंतर्गत अनेक कार्यक्रम व नवाचार सहकारिता के माध्यम से किये जा रहे है, जिसमे सहकारिता क्षेत्र की इकाई-समितियों को बहुउद्देशीय बनाना व इस आंदोलन को और विस्तारित करना है। सहकारिता की महत्ता को ध्यान में रखते हुए 2021 में केंद्र सरकार द्वारा पृथक से सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया, जो सहकारी आंदोलन के प्रति सरकार के सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है।

नई सहकारिता नीति : लोकसभा में बोले शाह- यह सहकारिता क्षेत्र के समग्र विकास का रोडमेप

■ केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बताया

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में जानकारी दी कि, केंद्र सरकार ने सहकारी क्षेत्र को नई दिशा देने के उद्देश्य से 24 जुलाई 2025 को नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 की घोषणा की है। यह नीति सहकारी संस्थाओं के व्यवस्थित और समग्र विकास के लिए एक व्यापक ढांचा और रोडमैप प्रदान करती है।

मंत्री ने बताया कि इस नीति का मुख्य मिशन अगले दस वर्षों में 16 प्रमुख उद्देश्यों को हासिल करना है। इन्हें छह रणनीतिक मिशन स्तंभों में विभाजित किया गया है। खास बात यह है कि नीति के अधिकांश बिंदुओं पर अमल की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। नीति के तहत पहला मिशन सहकारिता को मजबूती देने के लिए अनुकूल कानूनी और विनियामक वातावरण तैयार करना है, जिससे समितियों को अधिक स्वायत्तता, सुशासन और पारदर्शिता मिल सके। दूसरा मिशन सहकारी समितियों को अन्य आर्थिक संस्थाओं की तरह सुलभ और किफायती वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना और समान व्यावसायिक अवसर प्रदान करना है।

पेशेवर प्रशिक्षण तंत्र विकसित करने का प्रावधान : इसके अतिरिक्त नीति में सहकारी क्षेत्र के लिए कुशल मानव संसाधन और पेशेवर प्रशिक्षण का पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने का भी प्रावधान है। इसके अंतर्गत युवाओं को सहकारी उद्यमों में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना, मानकीकृत सहकारिता पाठ्यक्रम तैयार करना और प्रशिक्षकों व विजिटिंग फैकल्टी की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। सरकार का मानना है कि नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 से सहकारी समितियां भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में अधिक सक्षम होंगी और ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों तक आर्थिक सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाएंगी।

सहकारी समितियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने का प्रावधान

तीसरे स्तंभ में सहकारी समितियों के बीच सहयोग और नेटवर्किंग को बढ़ावा देने, उनके ढांचे को मजबूत करने और भौगोलिक पहुंच का विस्तार करने पर जोर दिया गया है। चौथा मिशन समितियों को भविष्य के लिए तैयार करना है, जिसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग, पेशेवर प्रबंधन और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। नीति का पांचवां स्तंभ समावेशिता और सदस्य-केंद्रितता को बढ़ावा देना है, ताकि सहकारी आंदोलन देश के हर कोने तक पहुंचे और युवाओं व महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सके। छठा मिशन सहकारी समितियों की नए और उभरते क्षेत्रों में भागीदारी सुनिश्चित करना तथा पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है।

लघु वनोपजों से आत्मनिर्भरता की राह, सीएम साय ने तय किया हरित विकास का रोडमैप

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में विगत दिनों मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित कलेक्टर- डीएफओ संयुक्त कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के वन प्रबंधन, तेंदूपत्ता संग्राहकों के हित, लघु वनोपजों के मूल्य संवर्द्धन (वैल्यू एडिशन), ईको-टूरिज्म, औषधीय पौधों की खेती और वनों से जुड़ी आजीविका के विविध आयामों पर विस्तृत चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहक हितग्राहियों की संख्या आज 12 लाख से अधिक हो चुकी है, जो हमारे सामूहिक प्रयासों की सफलता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आवश्यकता इस बात की है कि हम वन उपज का अधिकतम वैल्यू एडिशन करें। उन्होंने कहा कि राज्य में वन धन केंद्रों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, ताकि ग्रामीणों को अधिक आय के साधन मिल सकें और वे आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ें।

लघु वनोपज आधारित स्टार्टअप और वन धन केंद्रों को मिलेगा प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि लघु वनोपजों को वनांचल क्षेत्रों में आजीविका के प्रमुख साधन के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। बैठक में लघु वनोपज आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और वन धन केंद्रों को सुदृढ़ करने पर सार्थक चर्चा हुई, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल सके। छत्तीसगढ़ हर्बल और संजीवनी ब्रांड के उत्पादों के प्रचार-प्रसार पर विशेष बल दिया गया। बैठक में निर्देश दिए गए कि इन उत्पादों की बिक्री ग्रामीण और शहरी दोनों बाजारों में बढ़ाई जाए, ताकि स्थानीय उत्पादों के लिए एक मजबूत मार्केट नेटवर्क विकसित हो सके। साथ ही, उत्पादों के जैविक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने पर बल दिया गया। वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि पहली बार वन अधिकारियों की बैठक आयोजित कराने के लिए वे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि सभी कलेक्टर और वन अधिकारी समन्वय स्थापित कर संयुक्त रूप से कार्य करें, तो इसके अत्यंत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। वन मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि बस्तर और सरगुजा संभागों में विशेष रूप से ईको-टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसे आजीविका से जोड़ने के लिए ठोस रणनीति बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अब 75 प्रकार की लघु वनोपजों की खरीदी करने जा रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि लाख उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर है, और यदि ठोस कार्ययोजना बनाकर लक्षित रूप से कार्य किया जाए तो प्रदेश देश में प्रथम

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि प्रदेश में अब 46 प्रतिशत वन आवरण हो चुका है, जो लगभग दो प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि में कैम्पा योजना और "एक पेड़ मां के नाम" जैसी अभिनव पहल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कॉन्फ्रेंस में जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि तेंदूपत्ता संग्राहकों को भुगतान सात से पंद्रह दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। साथ ही भुगतान की जानकारी एसएमएस के माध्यम से सीधे संग्राहकों के मोबाइल पर भेजी जाए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। बैठक में बताया गया कि लगभग 15 लाख 60 हजार संग्राहकों की जानकारी ऑनलाइन दर्ज हो चुकी है और सभी भुगतान बैंक खातों के माध्यम से किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तेंदूपत्ता संग्रहण प्रक्रिया के पूर्ण कंप्यूटरीकरण की पहल को और तेज करने के निर्देश दिए।

कॉन्फ्रेंस में औषधीय पौधों की खेती के विस्तार हेतु प्रचार-प्रसार गतिविधियों को बढ़ाने और इसके लिए कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के मैदानी अमले की सहायता लेने पर भी चर्चा की गई।

औषधीय पौधों की खेती के विस्तार की नई पहल

बैठक में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। धमतरी, मुंगेली और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (जीपीएम) जिलों में औषधीय पौधों की खेती से संबंधित विषयों पर उपस्थित डीएफओ को विस्तृत जानकारी दी गई।

बैठक में बताया गया कि औषधीय पौधों की खेती न केवल लोगों की आजीविका बढ़ाने में सहायक होगी, बल्कि पारंपरिक उपचार पद्धतियों के ज्ञान को भी आगे बढ़ाएगी। औषधीय पादप बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) ने इस क्षेत्र में उपलब्ध संभावनाओं और लोगों की आय में वृद्धि के अवसरों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की।

सहकारिता के माध्यम से किसानों के जीवन में आ रही खुशहाली : डॉ. रमन

- चारों जिले के सहकारी बैंकों से 5 लाख 40 हजार किसान सहकारिता से हो रहे लाभान्वित
- कृषक उन्नति योजना के तहत 4559 करोड़ 66 लाख रूपए की राशि किसानों के बैंक खाते में की गई अंतरिती

किसान देश का सम्मान और किसानों से हो रही है देश की उत्तरोत्तर प्रगति : कश्यप

वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता, संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि देश के विकास के लिए जय जवान-जय किसान का अह्वान किया गया। किसान देश का सम्मान है और किसानों से देश की उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है और सभी सहकारिता से जुड़े है। सहकारिता का यह आंदोलन जन-जन तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप हमारा देश विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 2058 पैक्स है और कॉमन सर्विस सेंटर में सुविधाएं दी जा रही है। 532 नये पैक्स का गठन किया गया है। जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। सभी ग्राम पंचायतों में सहकारी समिति होनी चाहिए, ताकि किसानों को लाभ मिल सके।

राजनांदगांव। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने पद्मश्री गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम राजनांदगांव में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव द्वारा आयोजित सहकारी सम्मेलन में शिरकत की।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि राजनांदगांव, कबीरधाम, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान -गण्डई जिले से बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं कृषक यहां सहकारी सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे है। उन्होंने कहा कि सहकारिता में बहुत ताकत है। सहकारिता के माध्यम से किसानों के जीवन में खुशहाली एवं परिवर्तन आ रहे है। छत्तीसगढ़ में किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया गया, जिससे उनके जीवन में खुशहाली आयी। किसानों का जीवन पहले अधिया की भरपायी करते हुए निकल जाता था और साहुकारों के चंगुल में फंसकर ब्याज देते-देते परेशान हो जाते थे। सहकारिता एक चमत्कार है और केंद्रीय सहकारिता बैंक से चारों जिले के 5 लाख 40 हजार किसान सहकारिता से लाभान्वित हो रहे हैं। उनके जीवन में सहकारिता से जुडने पर महत्वपूर्ण परिवर्तन आए है। कृषक उन्नति योजना के तहत धान खरीदी अंतर्गत रिकार्ड तोड़ धान खरीदी की गई है और लगभग 4559 करोड़ 66 लाख रूपए की राशि कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में अंतरित की गई है। जिले में बैंकिंग सुविधाओं में बढ़ोत्तरी हुई है। एटीएम एवं माईक्रो एटीएम की सुविधा किसानों को मिल रही है। माईक्रो एटीएम के तहत पहले किसान 10 हजार रूपए निकाल सकते थे, अब इसकी क्षमता बढ़ाकर 20 हजार रूपए कर दिया गया है। इसी तरह रूपे डेबिट कार्ड से 20 हजार रूपए से क्षमता बढ़ा दी गई अब 40 हजार रूपए तक की राशि आहरण कर सकते है।

किसानों के आय में हुई वृद्धि : संतोष पांडे- सांसद श्री संतोष पाण्डेय ने कहा कि केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में देश में बैंकिंग सुविधाओं में वृद्धि हुई है। एटीएम की सुविधा बढ़ी तथा कम्प्यूटरीकरण से कार्यों में तेजी आयी है। किसानों की आय में वृद्धि हुई, बैंक खाते खुले तथा बचत एवं सहभागिता की प्रवृत्ति बढ़ी। सब मिलकर एवं संगठित होकर एक साथ कोई बड़ा कार्य करते है, तो वह सफल होता है। उन्होंने किसानों की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

सचिन बघेल ने किया प्रतिवेदन का वाचन

अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित श्री सचिन बघेल ने प्रतिवेदन का वाचन किया। उन्होंने बताया कि बैंक की अंशपूंजी 31 मार्च 2024 पर 19244.60 लाख रूपए थी, जो 31 मार्च 2025 में बढ़कर 20557.82 लाख रूपए हो गई है अर्थात अंशपूंजी में 1313.22 लाख रूपए की वृद्धि हुई है। निधियों में 5636.66 लाख रूपए की वृद्धि हुई है। 31 मार्च 2025 पर बैंक का शुद्ध लाभ 2123.56 लाख रूपए एवं संचित लाभ 5830.43 लाख रूपए है। 31 मार्च 2025 पर बैंक का एनपीए 4244.25 लाख रूपए है, जो कुल ऋण का 6.24 प्रतिशत है। बैंक द्वारा वर्ष 2024-25 में कृषकों को 160529.88 लाख रूपए का ऋण वितरण किया गया है। बैंक के कार्यक्षेत्र में कुल 275 खाद केन्द्र संचालित है। जिसके माध्यम से कृषकों को खाद उठाव करने में सुविधा प्राप्त हो रही है।

इनकी रही मौजूदगी

इस अवसर पर विधायक पंडरिया श्रीमती भावना बोहरा, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक श्री केदार नाथ गुप्ता, राजनांदगांव जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नम्रता सिंह, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री विक्रांत सिंह, पूर्व विधायक श्री विनोद खांडेकर, पूर्व विधायक श्री कोमल जंघेल, पूर्व विधायक श्री मोतीलाल चंद्रवंशी, पूर्व विधायक श्री रामजी भारती, श्री कोमल सिंह राजपूत, श्री प्रदीप गांधी, श्री रमेश पटेल, श्री दिनेश गांधी, श्री राजेंद्र चंद्रवंशी, श्री खूबचंद पारख, श्री संतोष अग्रवाल, श्री सुरेश एच लाल, श्री राजेन्द्र गोलछा सहित राजनांदगांव, कबीरधाम, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले के जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में कृषकगण उपस्थित थे।

किसानों को 6636 करोड़ रुपए का मिला ब्याज मुक्त ऋण

- सभी 2058 पैक्स सोसायटियो में पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित
- किसानों को डेयरी, मत्स्य पालन और वनोपज प्रसंस्करण से जोड़ने पर दें विशेष ध्यान: श्री गुप्ता

पैक्स सोसायटियों में 2058 माइक्रो एटीएम स्थापित

बैठक में यह भी बताया गया कि, राज्य के सहकारी बैंकों में 262 एटीएम और सभी पैक्स सोसायटियों में 2058 माइक्रो एटीएम स्थापित किए गए हैं। साथ ही किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी 2058 पैक्स सोसायटियो को पीएम किसान समृद्धि केंद्र बनाए गए। इससे किसानों को आसानी से अपने खाते से राशि निकालने की सुविधा मिल रही है। बैठक में नाबार्ड के उप महाप्रबंधक श्री अजय थुटे, अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री के.एन. कांडे, संयुक्त पंजीयक श्री उमेश तिवारी, उप पंजीयक व महाप्रबंधक श्री युगल किशोर, ओएसडी श्री अविनाश श्रीवास्तव, एजीएम श्री अरुण पुरोहित, एजीएम श्री एल के चौधरी और अन्य बैंक के अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में चालू खरीफसीजन में किसानों को 6636 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया जा चुका है। ब्याज मुक्त ऋण वितरण से 14 लाख 96 हजार किसान लाभान्वित हुए है। यह जानकारी अपेक्स बैंक के प्राधिकृत अधिकारी श्री केदार नाथ गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में दी गई।

अपेक्स बैंक की बोर्ड की बैठक में श्री केदार नाथ गुप्ता ने कहा कि डेयरी, मत्स्य पालन और वनोपज प्रसंस्करण जैसी रोजगार आधारित योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने खाद की उपलब्धता और वितरण की समीक्षा करते हुए कहा सहकारिता के अंतर्गत कि इस साल खरीफसीजन के लिए राज्य सरकार ने 10.72 लाख मेट्रिक टन खाद वितरण का लक्ष्य रखा है, और अब तक 8 लाख 69 हजार मेट्रिक टन खाद का भंडारण किया गया है। इनमें से 8 लाख 01 हजार मीट्रिक टन खाद किसानों को वितरित किया जा चुका है। समितियों के गोदामों में 67 हजार मेट्रिक टन खाद उपलब्धता है।

सहकारी एवं निजी क्षेत्रों में 15.64 लाख टन खाद का भंडारण

प्रदेश में चालू खरीफ सीजन के लिए भारत सरकार ने 14.62 लाख टन रासायनिक खाद का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके विरुद्ध सहकारी एवं निजी क्षेत्रों में 15.64 लाख टन का भंडारण कर लिया गया है। भंडारण के आधार पर किसानों को अब तक 13.19 लाख टन खाद वितरित किया गया है। यह व्यवस्था बताती है कि समितियों और निजी क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं और किसानों को किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि, खरीफ सीजन में किसानों को खाद की आपूर्ति उनकी समयबद्ध जरूरतों के अनुरूप प्राथमिकता से की जा रही है।

सहकारिता के क्षेत्र में हो रहे चमत्कारिक परिवर्तन : डा. रमन

किसानों की समृद्धि की दिशा में काम कर रही सरकार : केदार कश्यप

रायपुर। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में सहकारिता का बीजारोपण करने वाले महान विभूतियों को पुण्य स्मरण करते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि, छत्तीसगढ़ में श्री वामनराव लाखे और ठाकुर प्यारेलाल जैसे पुरोधाओं ने सहकारिता की नींव रखी, जिसका विकसित स्वरूप आज हम सभी देख रहे हैं। यह वर्ष सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, और केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के प्रयासों से निश्चित रूप से इस क्षेत्र में चमत्कारिक परिवर्तन हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय के अथक प्रयासों से प्रदेश के किसानों के जीवन में खुशहाली आई है। पूरे देश में वे पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने प्रति एकड़ 21 क्विंटल और 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय ने सहकारिता को राज्य के अंतिम गांव तक पहुंचाने का कार्य किया है। अपेक्स बैंक प्रदेश में 40 हजार करोड़ रुपए के टर्नओवर के साथ सबसे शक्तिशाली संगठन है और इसके माध्यम से अब तक 7 हजार 5 सौ करोड़ रुपए का ऋण किसानों को उपलब्ध कराया गया है।

प्रदेश के सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री साय किसानों की समृद्धि के चिंतन पर हमेशा बल देते हैं। अपने मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में डॉ. रमन सिंह ने किसानों को भरपूर सम्मान दिया, उनकी समृद्धि की चिंता की, आज मुख्यमंत्री श्री साय उसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश सरकार की धान खरीद नीति की चर्चा करते हुए श्री कश्यप ने कहा कि प्रदेश के 2,739 उपार्जन केंद्रों के जरिए प्रदेश में 149 लाख मीटरिक टन धान खरीदा गया है। प्रदेश सरकार इसके अलावा दुग्ध, मत्स्य, लघु वनोपज समितियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और अभी प्रदेश में 711 इन समितियों को गठन हुआ है तथा 530 नई अपेक्स समितियाँ और गठित की जा रही हैं। श्री कश्यप ने कहा कि किसानों के सहयोग और सहकार से समृद्धि तक पहुँचना है क्योंकि बिना सहकार, नहीं उद्धार।

गणतंत्र दिवस पर निकली सहकारिता विभाग की झांकी, सहकार से समृद्धि की ओर रखी गई थीम

रायपुर। 77 वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में विभिन्न विभागों द्वारा झांकियां प्रस्तुत की गई। सहकारिता विभाग द्वारा भी अंजोर विजन 2047 सहकार से समृद्धि की ओर विषय पर झांकी प्रदर्शित की गई।

झांकी में छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारिता के माध्यम से हो रहे समावेशी, सतत एवं जन-केंद्रित विकास की सशक्त झलक प्रस्तुत गई। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर सहकारी क्षेत्र में भारत टैक्सी, गैस गोडाउन, पेट्रोल पम्प स्थापना कर वर्ष 2047 तक अंजोर विजन में सहकारिता विभाग के द्वारा रोजगार के नये अवसर सृजित कर युवाओं, महिलाओं, कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य एवं सहकारिता क्षेत्र में अंजोर विजन 2047 के परिप्रेक्ष्य में किये जा रहे इन नवाचारों को इस झांकी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है।

छत्तीसगढ़ सहकार की धरती

झांकी के माध्यम से छत्तीसगढ़ की धरती सहकार की धरती है। यहाँ खेती अकेले नहीं होती, यहाँ विकास सहभागिता से होता है। सहकारिता ने किसान को सम्मान दिया, महिला को आत्मनिर्भर बनाया, और आदिवासी समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा। सहकारिता विभाग द्वारा पैक्स के माध्यम से किये जा रहे कार्यो को भी झांकी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया, जिसमें राज्य में वर्तमान में 2058 प्राथमिक कृषि साख समितियाँ (क्ष्ष्ट्स) सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। ये समितियों किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण, बीज, उर्वरक, कीटनाशक तथा अन्य आवश्यक सेवाएँ समय पर उपलब्ध करा रही है, किसानों की सुविधा के लिए पैक्स पुनर्गठन योजना 2025 अंतर्गत 515 नवीन पैक्सों का गठन किया गया है। जिसे अंजोर विजन 2047 के परिप्रेक्ष्य में 01 अप्रैल 2026 से कार्यशील करने की कार्यवाही जारी है।

मक्का प्रसंस्करण केन्द्र, शक्कर कारखाना कवर्धा का माडल दिखाया गया

÷सहकार से समृद्धि÷ के राष्ट्रीय विजन् के अनुरूप, अंजोर विजन 2047 के अंतर्गत पैक्स में प्रधानमंत्री जनऔषधि केन्द्र, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र, सीएससी, माईक्रो एटीएम छत्तीसगढ़ में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत क्ष्ष्ट्स् स्तर पर गोदामों एवं भंडारण अवसंरचना का निर्माण हो रहा है, जिससे किसानों को अपनी उपज सुरक्षित रखने और उचित समय पर बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिल रही है। सहकारिता को पारदर्शी एवं सुदृढ़ बनाने हेतु राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के माध्यम से सहकारी संस्थाओं का डिजिटलीकरण एवं डेटा संधारण तकनीक को दर्शाया गया। झांकी में मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण केन्द्र कोण्डागांव एवं भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा के माडल का प्रदर्शित किया गया।

कोकोड़ी एथेनॉल प्लांट से शेयरधारक किसानों की आय बढ़ी

रायपुर। माँ दंतेश्वरी मक्का सहकारी समिति कोण्डागांव द्वारा संचालित एथेनॉल प्लांट कोकोड़ी क्षेत्र के शेयरधारक किसानों के लिए आय बढ़ाने का मजबूत माध्यम साबित हो रहा है। प्लांट से जुड़े किसानों को मक्का विक्रय पर बाजार भाव की तुलना में 700 से 800 रुपये प्रति क्विंटल तक अतिरिक्त लाभ मिल रहा है, जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

एथेनॉल प्लांट के संचालन के बाद समिति द्वारा शेयरधारक किसानों से प्राथमिकता के आधार पर मक्का की खरीद की जा रही है। इस वर्ष भी किसानों को मक्का का बेहतर मूल्य देकर उनकी मेहनत का उचित प्रतिफल सुनिश्चित किया गया है। वर्तमान में खुले बाजार में मक्का का भाव 1600 से 1700 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि एथेनॉल प्लांट कोकोड़ी द्वारा शेयरधारक किसानों से 2400 रुपये प्रति

क्विंटल की आकर्षक दर पर मक्का की खरीद की जा रही है। इससे किसानों को बाजार भाव की तुलना में सीधा आर्थिक लाभ मिल रहा है। बाजार भाव 1600 रूपए प्रति क्विंटल है, जबकि प्लांट दर 2400 रूपए प्रति क्विंटल है, अतिरिक्त लाभ 800 प्रति क्विंटल है। उदाहरण के तौर पर 40 क्विंटल मक्का विक्रय पर किसान को कुल अतिरिक्त आय 32 हजार रूपए की अतिरिक्त आय प्राप्त होगी।

स्थानीय किसानों ने बताया कि एथेनॉल प्लांट जुड़ने के बाद खेती अधिक लाभकारी बनी है। एक किसान ने कहा, 800 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त लाभ मिलने से हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और खेती में उत्साह बढ़ा है। समिति के पदाधिकारियों के अनुसार यह लाभांश मॉडल किसानों की आर्थिक उन्नति को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है, जिससे अधिक से अधिक किसान मक्का उत्पादन को बढ़ावा देकर सहकारी व्यवस्था से जुड़े सकें। आज तक 203 किसानों को राशि रुपये 1.45 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है, वर्तमान में खरीदी जारी है। एथेनॉल प्लांट कोकोड़ी के संचालन से न

सहकारिता विभाग का स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

रायपुर। इस बार राज्योत्सव-2025 में सहकारिता विभाग का स्टॉल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। इस वर्ष स्टॉल की थीम 25 वर्षों की यात्रा और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 रखी गई थी, जिसके तहत विभाग ने अपनी उपलब्धियाँ और नवाचार प्रदर्शित किए हैं। राज्योत्सव में आने वाले आगंतुकों ने सहकारिता विभाग के इस स्टॉल को राज्य के सहकारी विकास की प्रेरणादायक झलक बताया। यह स्टॉल छत्तीसगढ़ के किसानों की आत्मनिर्भरता और सामूहिक सहयोग की भावना का सशक्त प्रतीक बन गया है। प्रदर्शनी में यह दर्शाया गया है कि सहकारिता आंदोलन ने पिछले 25 वर्षों में किसानों, श्रमिकों और आम नागरिकों के जीवन में किस प्रकार आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाया है। स्टॉल में सहकारी शक्कर कारखानों, इथेनाल संयंत्रों, प्राथमिक कृषि साख समितियों, धान उपार्जन प्रणाली, किसान क्रेडिट कार्ड योजना और सहकारी बैंकों में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जैसी प्रमुख उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया था।

विभागीय गतिविधियों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया

स्टॉल में **'सहकार से समृद्धि'** की भावना को फोटो, चार्ट और डिजिटल माध्यम से जीवंत रूप में प्रदर्शित किया गया है। 'अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025' के अंतर्गत राज्य में आयोजित गतिविधियों जैसे ड्रोन तकनीक प्रदर्शन, किसान संगोष्ठियाँ, जैविक सप्ताह, वृक्षारोपण अभियान और फार्मर पंजीयन की जानकारी भी दी गई है।

शाह ने भव्य कार्यक्रम में सहकारी टैक्सी मॉडल का किया शुभारंभ

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारत की पहली सहकारिता-आधारित टैक्सी सेवा 'भारत टैक्सी' का औपचारिक शुभारंभ किया।

इस अवसर पर केन्द्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, मुरलीधर मोहोल, सहकारिता सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी सहित अनेक व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम में देशभर से आए 1,200 से अधिक "सारथियों" (ड्राइवर पार्टनर्स) की भागीदारी ने इस मॉडल को लेकर व्यापक समर्थन को दर्शाया।

सहकारिता मंत्रालय ने बनाया नया माडलः कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए मालिकाना हक आधारित मॉडल विकसित कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार टैक्सी व्यवसाय में नहीं, बल्कि सहकारिता टैक्सी क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, जहां असली मालिक ड्राइवर स्वयं होंगे। उन्होंने कहा कि अगले तीन वर्षों में कश्मीर से कन्याकुमारी तक सहकार टैक्सी टैक्सी सारथियों के कल्याण का बड़ा माध्यम बनेगी।

टैक्सी का पहिया सारथियों की समृद्धि, आत्मसम्मान का माध्यम बनेगा

उन्होंने कहा कि, अब तक टैक्सी का पहिया किसी और की कमाई बढ़ाता था, लेकिन अब वही पहिया सारथियों की समृद्धि और आत्मसम्मान का माध्यम बनेगा। हर पांच वर्ष में चुने गए सारथी प्रतिनिधि बोर्ड में बैठकर फैसले लेंगे, जो सहकारिता की सच्ची भावना को दर्शाता है। भारत टैक्सी में चार पहिया, तीन पहिया और दो पहिया वाहन शामिल होंगे। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए 'सारथी दीदी' अवधारणा शुरू की गई है, जिसमें महिलाएं केवल महिला ड्राइवर के साथ सुरक्षित यात्रा कर सकेंगी।

यह सहकारिता का उत्कृष्ट माडलः शाह ने कहा कि भारत टैक्सी संभवतः दुनिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां किसी व्यक्ति या कंपनी के बजाय सारथी ही सहकारी संस्था के वास्तविक मालिक हैं। मात्र 500 रुपये की शेयर पूंजी से जुड़कर ड्राइवर मालिक बनते हैं। भारत टैक्सी कुल मुनाफे का केवल 20 प्रतिशत परिचालन के लिए रखेगी, जबकि शेष आय सीधे सारथियों के खाते में जाएगी। कोई प्लेटफॉर्म फीस या भारी कमीशन नहीं लिया जाएगा और ग्राहक द्वारा किया गया भुगतान तुरंत ड्राइवर के खाते में ट्रांसफर होगा।

भारत टैक्सी का कई संस्थाओं के साथ एमओयूः शाह ने बताया कि, भारत टैक्सी ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, डीएमआरसी, एयरपोर्ट अथॉरिटी, आईएफएफसीओ टोकियो, एसबीआई, पेटीएम सहित नौ प्रमुख संस्थाओं के साथ एमओयू किए हैं। इन समझौतों से डिजिटल भुगतान, बीमा, फाइनेंस, एयरपोर्ट और मेट्रो कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं मजबूत होंगी। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी केवल एक सेवा नहीं, बल्कि स्वामित्व, सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि पर आधारित एक नया सहकारी प्रयोग है, जो देश के लाखों गिग वर्कर्स के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा।

15.55 लाख किसानों को दिया गया शून्य ब्याज पर 7.667 करोड़ का ऋण : केदार कश्यप

- **सहकारिता मंत्री ने राजधानी में की पत्रकारों से चर्चा, बताया-25 लाख 24 हजार किसानों से 141 लाख 4 हजार मीट्रिक टन धान खरीदा गया, 31 हजार 275 करोड़ का भुगतान हुआ**

रायपुर। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने राजधानी रायपुर में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि, प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर वर्ष 2025-26 में कृषि ऋण वितरण हेतु 9 हजार करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरूद्ध 7 हजार 667 करोड़ का ऋण वितरण किया जा चुका है। ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों की संख्या 15 लाख 55 हजार है। खरीफ सीजन वर्ष 2025-26 में 25 लाख 24 हजार किसानों से 141 लाख 04 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी समितियों के माध्यम से की गई। किसानों को धान खरीदी की राशि 31 हजार 275 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

515 नई पैक्स समितियों का गठन

सहकारिता मंत्री बताया कि, सहकार से समृद्धि के अंतर्गत 515 नई पैक्स समितियों का गठन किया जा चुका है, साथ ही 351 डेयरी सोसायटी, 322 फिशरीज सोसायटी, 153 वनोपज सोसायटी सहित कुल 1341 सहकारी समितियों का गठन हो चुका है। राज्य के 2058 पैक्स समितियों में से 2028 समितियों का कम्प्यूटराईजेशन किया जा चुका है। राज्य में 2058 पैक्स समितियों में माईक्रो ए.टी.एम. लगाए जा चुके हैं, जिनसे 230 करोड़ रूपये का ट्रान्जेक्शन हो चुका है। पैक्स के सामान डेयरी समितियों में भी माईक्रो ए.टी.एम. उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

दो साल में सहकारी बैंकों की 16 नई शाखाएं खुलीं

विगत 2 वर्ष में अपेक्स बैंक और जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों की 16 नवीन शाखाएं खोली गई है। वर्तमान में 345 शाखाएं कार्यरत हैं। सहकारी बैंको में ग्राहकों की सुविधा के लिए बैंक ब्रांच स्तर पर 169 नवीन ए.टी.एम. मशीन भी लगाये गये हैं। राज्य में सहकारिता क्षेत्र अंतर्गत 04 सहकारी शक्कर कारखाने कार्यरत हैं, जिनसे 55 हजार से अधिक गन्ना उत्पादक किसान जुड़े हुए हैं। वर्ष 2024-25 में 6.92 लाख मीट्रिक टन गन्ने की खरीदी एवं 67 हजार मीट्रिक टन शक्कर का उत्पादन किया गया है। गन्ना विक्रेता किसानों को 290 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है। छ.ग. के शक्कर कारखानों का औसत शक्कर रिकवरी दर 11.20 प्रतिशत है, जो देश के औसत शक्कर रिकवरी दर 9.28 प्रतिशत से काफी अधिक है।

सरगुजा संभाग में 100 बसें चलाने का लक्ष्य

परिवहन मंत्री श्री कश्यप ने बताया कि, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना 2025 के तहत प्रथम चरण में बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिलों में 100 बस चलाने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना के तहत ऐसे ग्रामों को जहॉं पूर्व में बस सुविधा उपलब्ध नहीं है ऐसे ग्रामों को जनपद मुख्यालय/नगरीय क्षेत्र/तहसील मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय को जोड़ना।

प्रदेश में सहकारी समितियों की संख्या बढ़ कर हुई 2 हजार 573

मुख्यमंत्री ने किया 515 नई पैक्स समितियों का वर्चुअल शुभारभ

- सीएम साय ने कहा है कि सहकार से समृद्धि के संकल्प को साकार करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित होंगे नवगठित पैक्स
- किसानों को आसानी से मिलेगी खाद, बीज और अल्पकालीन ऋण की सुविधा

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन से प्रदेश की नवगठित 515 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) का वर्चुअल शुभारंभ कियाउन्होंने इसे प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी सौगात बताते हुए कहा कि सहकार से समृद्धि के संकल्प को साकार करने की दिशा में यह कदम ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नई समितियों के शुरू होने से अब पूरे प्रदेश में सहकारी समितियों की संख्या बढ़कर 2 हजार 573 हो गई है।

अब पैक्स समितियां बहुउद्देश्यीय सोसायटी के रूप में कार्य करेंगी

उन्होंने प्रदेश के अन्नदाता किसानों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार खेती-किसानी में आधुनिक तकनीक और सहकारिता के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा दे रही है, ताकि गांव और किसान समृद्ध बन सकें। उन्होंने बताया कि अब पैक्स समितियां बहुउद्देश्यीय सोसायटी के रूप में कार्य करेंगी, जिससे किसानों को खाद, बीज और अल्पकालीन ऋण जैसी सुविधाएं उनके गांव के पास ही उपलब्ध होंगी। साथ ही धान बेचने की प्रक्रिया भी आसान होगी और किसान अपनी नजदीकी समिति में ही धान बेच सकेंगे।

प्रदेश की 2058 समितियों को कम्प्यूटरीकृत किया गया

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पहले से कार्यरत 2058 समितियों को बेहतर सेवाएं देने के लिए कंप्यूटरीकृत किया गया है और इनमें माइक्रो एटीएम भी लगाए गए हैं, जिनसे किसान 20 हजार रुपये तक की राशि निकाल सकते हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि नवगठित 515 समितियों में से 197 समितियां आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित की गई हैं, जिससे दूर-दराज के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

सहकारी समितियों में एक ही स्थान पर 25 से अधिक सरकारी सेवाए उपलब्ध

उन्होंने कहा कि ये समितियां केवल खाद-बीज वितरण तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि भविष्य में दुग्ध उत्पादन, मछली पालन जैसे सहायक कृषि गतिविधियों से भी जुड़ेंगी। साथ ही समितियों में लोक सेवा केंद्र भी शुरू किए जाएंगे, जहां एक ही स्थान पर 25 से अधिक सरकारी सेवाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की कि वे इन समितियों के सदस्य बनकर इसका अधिकतम लाभ उठाएं और इनके संचालन में सक्रिय भागीदारी निभाएं।

इस अवसर पर सहकारिता मंत्री केदार कश्यप वर्चुअल उपस्थित रहे, साथ ही कृषि मंत्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल, रोजगार एवं कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, अपेक्स बैंक के प्राधिकृत अधिकारी केदारनाथ गुप्ता, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत तथा सचिव सहकारिता सी.आर. प्रसन्ना, सहकारिता विभाग के प्रबंध संचालक के.एन. कांडे सहित विभिन्न जिलों से लगभग 2500 जनप्रतिनिधिगण, किसान और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

बस्तर से हुई राज्य सहकारी संघ के साल 2026-27 के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत

- प्रशिक्षण से लैम्प्स प्रबंधन होगा सशक्त, सहकार से समृद्धि अभियान को मिलेगी रफ्तार
- प्रशिक्षित स्टाफसे अंतिम छोर तक पहुंचेगी सेवाओं की रोशनी

जगदलपुर। बस्तर में सहकारिता के जरिए ग्रामीण विकास की नई कहानी लिखने की तैयारी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित रायपुर के प्रशिक्षण केंद्र द्वारा आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ने लैंप्स (लार्ज एरिया मल्टीपर्पज सोसायटी) संस्थाओं को नई ऊर्जा और दिशा देने का काम किया है। इस पहल का उद्देश्य सिर्फ प्रशिक्षण तक सीमित नहीं, बल्कि गांव-गांव तक योजनाओं की रोशनी पहुंचाना है।

सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित रायपुर द्वारा सहकारिता विभाग एवं प्रबंध संचालक श्रीमती पूर्णिमा सिंह के दिशा-निर्देश व मुख्य कार्यपालन अधिकारी पीसी ध्रुव के मार्गदर्शन में साल 2026-27 के लिए तैयार किये गये वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसार माह अप्रैल 2026 में बस्तर संभाग से इसकी शुरूवात की गई। बस्तर अंचल में कार्यरत लैम्प्स संस्थाओं के प्रबंधकों और अधिकारियों के लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यवहारिक ज्ञान और दक्षता बढ़ाने का प्रभावी मंच साबित हुआ है।

सहकारिता के सिद्धांत और प्रबंधन की बारीकियां सिखाई: इस प्रशिक्षण के माध्यम से लैम्प्स संस्थाओं को आधुनिक तकनीक, प्रबंधन कौशल और सहकारी सिद्धांतों की गहन समझ प्रदान की जा रही है, जिससे वे ग्रामीण स्तर पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभा सकें। कार्यक्रम में पैक्स कम्प्यूटरीकरण, सहकारी लेखांकन तथा शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर प्रतिभागियों को व्यावहारिक रूप से सक्षम बनाया जा रहा है। प्रशिक्षण सत्रों में विशेषज्ञों द्वारा सहकारिता के मूल सिद्धांत, इसकी प्रासंगिकता और भारत सरकार की योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया जा रहा है। इससे यह उम्मीद जताई जा रही है कि प्रशिक्षण प्राप्त स्टाफ गांव-गांव में सहकारिता की पहुंच को और अधिक सुदृढ़ करेंगे तथा अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने में सफल होंगे।

सहकारिता को जन आंदोलन बनाने का आह्वान : संभाग के संयुक्त आयुक्त सहकारिता विनोद कुमार बुनकर ने सहकारिता को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। प्रशिक्षण के दौरान लैम्प्स प्रबंधक-मुख्य पर्यवेक्षक एसएस राज, तकनीकी अधिकारी आरिफ खान एवं सामान्य सहायक हितेश जैन ने पैक्स कम्प्यूटरीकरण एवं सहकारी लेखांकन पर मार्गदर्शन दिया। सत्र समन्वयक विवेकानंद झा, सहायक सत्र समन्वयक विवेक पांडे एवं मिथुन पाणिग्राही द्वारा सहकारिता मिथुन के सिद्धांतों पर प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में विपणन अधिकारी एसके कन्नौजिया, मनोज सिंह सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

प्रशिक्षण से बदलेगा सहकारिता का परिदृश्य : दो दिवसीय इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए लैम्प्स संस्थाओं के प्रबंधकों को तकनीकी दक्षता, पारदर्शी लेखांकन और योजनाओं के प्रभावी संचालन की विस्तृत जानकारी दी जा रही है, जिससे वे ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकें। यह पहल सहकारिता को केवल संस्था तक सीमित न रखकर जन-जन तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो "सहकार से समृद्धि "के लक्ष्य को साकार करने में मील का पत्थर साबित हो सकती है।

अर्थव्यवस्था को सशक्त करने का प्रभावी मॉडल : दिनेश कश्यप

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, जगदलपुर में अयोजित कार्यक्रम में पूर्व सांसद एवं बैंक के अध्यक्ष दिनेश कश्यप ने कहा सहकारिता तभी मजबूत होगी जब उससे जुड़े कर्मचारी प्रशिक्षित और जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित स्टाफके माध्यम से ही योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंच सकता है। सहकार से समृद्धि केवल नारा नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने का प्रभावी मॉडल है, जो किसानों और छोटे व्यापारियों के जीवन में ठोस बदलाव ला सकता है। बस्तर जैसे वनांचल क्षेत्र में सहकारिता का महत्व और भी बढ़ जाता है, जहां बड़ी आबादी कृषि और वनोपज पर निर्भर है। ऐसे में सहकारी संस्थाएं किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा कवच का काम करती हैं। यह प्रशिक्षण उसी दिशा में एक मजबूत कदम है, जो आने वाले समय में ग्रामीण विकास की तस्वीर बदल सकता है।

बस्तर में श्वेत क्रांति : आदिवासी परिवारों को मिलेगी गाय-भैंस, अमूल जैसा बड़ा डेयरी नेटवर्क

- बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक : चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सहकारिता मंत्री ने तैयार की रणनीति
- चारों राज्य केन्द्रीय गृह मंत्रालय के प्रारूप के अनुरूप 1930 साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन के कॉल सेंटर को अपडेट करें

रायपुर। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सहित इन सदस्य राज्यों और केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। यह बैठक केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत अंतर-राज्य परिषद सचिवालय द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार की मेज़बानी में आयोजित की गई।

नक्सलमुक्त बस्तर में बैठक होना हर्ष का विषय : शाह

बैठक को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि, यह बहुत हर्ष का विषय है कि यह बैठक बस्तर में आयोजित की जा रही है और इससे पहले ही आज पूरा बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि आज भारत के नक्सल मुक्त होने का संपूर्ण श्रेय हमारे सुरक्षाबलों के जवानों के परिश्रम और बहादुरी को जाता है। हमारी एजेंसियों ने बहुत सटीकता के साथ इनपुट एकत्र किए, सभी राज्यों के पुलिसबलों और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के साथ मिलकर हर इनपुट पर सटीक कार्रवाई करने से संबंधित समयबद्ध निर्णय किए। इसके साथ ही Whole of the Government Approach के साथ सभी राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के सभी विभागों ने नक्सलमुक्त हुए क्षेत्रों में विकास को पहुंचाने का काम किया।

छत्तीसगढ़ मध्य भारत का महत्पूर्ण राज्य

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि, मध्य क्षेत्रीय परिषद में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य हैं। उत्तर के हिमालय क्षेत्र से लेकर गंगा-यमुना के मैदानी भूभाग से लेकर मध्य भारत के पठारी, वन समृद्ध और खनिज समृद्ध क्षेत्र इस क्षेत्र में आते हैं, जो निश्चित रूप से देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होने कहा कि यह क्षेत्र हमें देश के अनाज के भंडारों को भरने में बड़ी मदद करता है। इस क्षेत्र के समृद्ध खनिज भंडार से देश के विकास को गति मिलती है और इसी क्षेत्र की समृद्ध विरासत और संस्कृति ने देश को आगे बढ़ाने में मदद की है। इसी क्षेत्र में देश के आस्था के सभी केंद्र करीब-करीब एक ही जगह पर आए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ लगभग सात राज्यों को जोड़ता है और इस दृष्टि से पूरे मध्य क्षेत्र का बहुत महत्व है। गृह मंत्री ने कहा कि आज यह पूरा क्षेत्र ना केवल नक्सल मुक्त हुआ है, बल्कि विवादों से भी मुक्त हुआ है, जो हम सबके लिए बहुत हर्ष का विषय है।

जल जीवन मिशन -2 पर अभी से फोकस करना होगा

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन -2 पर हमें अभी से फोकस करना चाहिए और हर घर में नल से जल पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, पोषण और समाज कल्याण बहुत संवेदनशील मुद्दे हैं। गृह मंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों और सभी मुख्य सचिवों से आह्वान किया कि कुपोषण के खिलाफ भारत सरकार की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल ड्रॉपआउट दर और स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी और अधिक कार्य हों। वित्तीय समावेशन और बिजली सुधार इस विकसित क्षेत्र को पूर्ण विकसित बनाने में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं।

बस्तर में सहकारिता मॉडल पर डेयरी विकास योजना लागू की जायेगी

इस बैठक में सहकारिता मंत्री अमित शाह की नेतृत्व में कई अहम फैसले हुए हैं। केंद्रीय गृहमंत्री ने बस्तर के विकास के लिए सहकारिता आधारित विशेष मॉडल तैयार किया गया है। बस्तर में स्थानीय आदिवासी परिवारों की आर्थिक स्थिति को तेजी से मजबूत करने सहकारिता मॉडल पर डेयरी विकास योजना लागू की जाएगी।

शाह ने योजना के बारे में बताया कि इसके तहत बस्तर के प्रत्येक आदिवासी परिवार को एक गाय और एक भैंस उपलब्ध कराने की तैयारी हो चुकी है। गुजरात के प्रसिद्ध अमूल मॉडल की तर्ज पर बस्तर के गांव-गांव में दुग्ध संग्रहण केंद्र, प्रोसेसिंग प्लांट और बेहतरीन मार्केटिंग की व्यवस्था विकसित की जाएगी, ताकि वनांचल के ग्रामीणों को उनके दूध का उचित और सबसे ज्यादा मूल्य मिल सके।

बस्तर में इस बड़े पशुधन वितरण और डेयरी नेटवर्क को विकसित करने के लिए देश की संबंधित बड़ी एजेंसियों के साथ आधिकारिक एमओयू भी हो चुका है।

सभी एजेंडा विकास की मॉनिटरिंग से थे संबंधित

श्री अमित शाह ने कहा कि, राज्यों के बीच के और राज्यों और केन्द्र के बीच के सभी विवादित मुद्दे समाप्त कर हम आज एक अच्छे वातावरण में यह बैठक कर रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि, आज की बैठक में सभी एजेंडा विकास की मॉनिटरिंग से संबंधित थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा संघीय ढांचा मजबूत हुआ है और क्षेत्रीय परिषद की बैठकें निरंतर हो रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप बहुत बड़े भूभाग में चार राज्यों के बीच और चार राज्यों का केन्द्र के साथ कोई विवाद ही नहीं बचा है, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

क्षेत्रीय परिषद बैठकों का एक मजबूत और जीवंत तंत्र बना

श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में क्षेत्रीय परिषद बैठकों का एक मजबूत और जीवंत तंत्र बना है - हमने इसे निर्णायक, निरंतर और परिणामदायी बनाया है। 2004 से 2014 के 10 वर्षों में क्षेत्रीय परिषद की मात्र 11 बैठकें हुई थीं, जो 2014 से 2026 के बीच बढ़कर 32 हो गई हैं। पहले 10 वर्षों में स्टैंडिंग कमेटी की 14 बैठकें हुई थीं, जो इस अवधि में ढाई गुना बढ़कर 35 हुई हैं। उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 में मात्र 569 मुद्दों पर चर्चा हुई थी, जबकि 2014 से 2026 में 1729 मुद्दों पर चर्चा हुई है, और उनमें से लगभग 80% मुद्दों का सफल निराकरण भी कर लिया गया है। लंबित मुद्दों में से अधिकांश मॉनिटरिंग से संबंधित हैं, जिनमें किसी भी प्रकार का विवाद शेष नहीं है।

हमारा कम से कम 50% ध्यान ग्रामीण विकास पर हो

श्री अमित शाह ने कहा कि, शहरी नियोजन, जन स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन और बिजली सुधार के चारों क्षेत्र में भी और अधिक गति से कार्य करें। गृह मंत्री ने अपील की कि हमारा कम से कम 50% ध्यान ग्रामीण विकास और व्यक्ति को मजबूत बनाने वाली योजनाओं पर रहना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि हर 5 किलोमीटर के दायरे में बैंक की सुविधा उपलब्ध होना बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हमारी सभी योजनाएं Direct Benefit Transfer (DBT) आधारित हैं, इसीलिए सभी राज्यों को इस दिशा में ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है।

सहकारी आंदोलन को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की कोशिशों में जुटा विभाग

रायपुर। "सहकार से समृद्धि" के दृष्टिकोण को साकार करने, देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने जमीनी स्तर तक सहकारी समितियों की पहुंच को गहरा करने और सहकारी समितियों के प्रदर्शन, उत्पादकता और लाभप्रदत्ता को बढ़ाने के लिए, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विभिन्न पहल प्रारंभ किये गये हैं, जिनमें से प्रमुख पहल एवं उनमें राज्य की प्रगति निम्नानुसार है:-

पैक्स को बहु-उद्देशीय बनाने के लिए आदर्श उपविधियां -

पैक्स और लैम्प्स की आय के स्त्रोत बढ़ाने तथा 25 से अधिक क्षेत्रों जैसे डेयरी, मात्स्यिकी, भण्डारण इत्यादि में रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से भारत सरकार सहकारिता मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये आदर्श उप-विधि के ड्राफ्ट को प्रदेश के सभी 2058 पैक्स/लैम्प्स में अंगीकृत कर लिया गया है।

प्रत्येक ग्राम पंचायत में बहुद्देशीय सहकारी सोसाइटी की स्थापना -

भारत सरकार सहकारिता मंत्रालय द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत को सहकारी समितियों से जोड़ने तथा सहकारिता के लाभ को जन-जन तक पहुंचाने के लिये राज्य के सभी अनाच्छादित एवं अल्पसेवित ग्राम पचायतों में बहुद्देशीय पैक्स/ दुग्ध/ मत्स्य/ लघुवनोपज सहकारी समितियों के गठन की योजना प्रारंभ की गयी है। इस योजना में अकार्यशील/ परिसमापनाधीन समितियों को कार्यशील बनाने अथवा परिसमापित करने तथा शेष अनाच्छादित/ अल्पसेवित पंचायतों में नवीन बहुद्देशीय पैक्स/ दुग्ध/ मत्स्य/ लघुवनोपज सहकारी समितियों का गठन किया जाना है। योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2024-25 से वर्ष 2028-29 तक किया जाना है।

डिजिटाईजेशन ऑफ प्राईमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसाइटीज

सहकारी सोसाइटियों का कम्प्यूटरीकरण करने से सोसाइटियों में किसानों के सभी ऋण अमानत, खातों में व्याज की गणना तथा लेन-देन का हिसाब-किताब तातारीख पूर्ण रहेगा, जिससे किसानों को अपने खातों की सही जानकारी तत्काल प्राप्त हो जाएगी। प्रदेश में संचालित सभी 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों का कम्प्यूटरीकरण केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत किया जा रहा है, जिसके लिए प्रथम चरण में राज्य के 2028 समितियों का चयन किया गया है। योजना का क्रियान्वयन 2022-23 से प्रारंभ किया गया है। योजना अतर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा खर्च का अनुपात 60:40 है। योजनातर्गत डिजिटलाईजेशन में प्रति सोसाइटी रू. 03.91 लाख की लागत अनुमानित है। वर्तमान में राज्य के सभी चयनित पैक्स Go-Live स्तर में पहुंच गये हैं।

कॉमन सर्विस सेन्टर

भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय द्वारा सभी प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को कॉमन सर्विस सेन्टर के रूप में विकसित करने हेतु निर्देश दिए गये हैं। वर्तमान स्थिति में 2,573 पैक्स सोसाइटियों द्वारा आई.डी. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जा चुका है, जिनमें से 1988 आई डी. एक्टिव हो चुके हैं। वर्तमान स्थिति में राशि रु. 10.04 करोड़ का संव्यवहार किया गया है।

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र

ग्रामीण/ब्लॉक स्तर पर सस्ती जेनेरिक दवाईयों की आम लोगों के लिए उपलब्धता तथा पैक्स में आय एवं रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय द्वारा पैक्स समितियों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र खोले जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त अनुक्रम में राज्य के कुल 26 समितियों में स्टोर प्रारंभ कर लिया गया है।

प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र की स्थापना

पैक्स को खुदरा उर्वरक विक्रेता के रूप में कार्य करने एव कृषि संबंधी सभी आदानों और सेवाओं के लिए वनस्टॉप शॉप के रूप में विकसित करने तथा उर्वरक एवं कीटनाशक छिडकाव के लिए ड्रोन उद्यमी के रूप में कार्य देने आदि के लिए योजना प्रारंभ की गयी है। राज्य के सभी 2058 पैक्स में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है।

सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अन्न भण्डारण योजना

योजनान्तर्गत भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं यथा AIF, AMI, SWAM, MIDH, PMFME ÌÍæ PMKSY के अभिसरण से पैक्स में खरीदी केंद्र, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, ग्रामीण हाट सहित अनाज भण्डारण हेतु बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है। राज्य में RIDF योजनान्तर्गत निर्माणाधीन 200 मीट्रिक टन क्षमता के सभी 725 गोदामों को भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय द्वारा योजना में शामिल कर लिया गया है। जिसमें से 710 गोदामों का निर्माण किया जा चुका है।

राष्ट्रीय सहकारी निर्यात/जैविक/बीज सहकारी समिति की सदस्यता -

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत् तीन नई राष्ट्रीय सहकारी समितियां क्रमशः राष्ट्रीय सहकारी निर्यात समिति लिमिटेड, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड तथा राष्ट्रीय सहकारी जैविक समिति लिमिटेड की स्थापना एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में की गई है, जिनके द्वारा क्रमशः सहकारी क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने, एकल ब्राण्ड अंतर्गत उन्नत बीजों की खेती, उत्पादन व वितरण करने तथा प्रमाणित व प्रमाणिक जैविक उत्पादों के उत्पादन, वितरण व विपणन का कार्य किया जाएगा। राज्य की प्राथमिक, जिला तथा राज्य स्तरीय समितियां इन समितियों की सदस्य बन सकती हैं।

केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने ली बैठक : शाह बोले- देश की हर पंचायत में एक सहकारी समिति का गठन होगा

कृषि उत्पाद की बिक्री के लिए 'पैक्स' द्वारा नेफेड और एनसीसीएफ पोर्टल पर शत-प्रतिशत पंजीकरण हो

- **शाह ने छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में पानी समिति के रूप में 'पैक्स' का शुभारंभ भी किया**

रायपुर। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य में सहकारिता के विस्तार से संबंधित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में पानी समिति के रूप में प्राथमिक कृषि साख समिति का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, केन्द्रीय सहकारिता राज्यमंत्री श्री मुरलीधर मोहोल, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव, सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप और केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी भी उपस्थित थे। गृह एवं सहकारिता मंत्री ने 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत 'पीपल फॉर पीपुल' कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण और छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न विकास कार्यो का लोकार्पण भी किया।

हर पंचायत में एक सहकारी समिति बनेगी

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए देश की हर पंचायत में एक सहकारी समिति का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को संपूर्ण जनजातीय विकास के लिए एक नई पब्लिक डेयरी योजना बनानी चाहिए, जो पैक्स, डेयरी और मत्स्य की सहकारी संस्था का काम करेगी।

मक्के की खेती के लिए करें प्रोत्साहित

श्री अमित शाह ने कहा कि, इथेनॉल उत्पादन के लिए एनसीसीएफ नेफेड और राज्य के बीच अनुबंध होना चाहिए जिससे किसानों को मक्के की खेती के प्रति प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने कहा कि मक्के की खेती में लागत भी कम है और केन्द्र सरकार द्वारा किसानों का सारा मक्का अच्छे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। श्री शाह ने कहा कि किसानों के कृषि उत्पाद की बिक्री के लिए 'पैक्स' द्वारा नेफेड और एनसीसीएफ पोर्टल पर शत-प्रतिशत पंजीकरण होना चाहिए।

सभी चीनी मिलों में एथेनाल प्लांट लगाएं

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि हर मंडी के हर व्यापारी, 'पैक्स' और सहकारी संस्था का खाता जिला सहकारी बैंक में खोलना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ में 4 सहकारी चीनी मिलें हैं, जिनमें से सिर्फ एक मिल में इथेनॉल उत्पादन प्लांट है। श्री शाह ने कहा कि बाकी 3 सहकारी चीनी मिलों में 6 महीने के अंदर मल्टी-फीड इथेनॉल उत्पादन प्लांट लगाए जाएं, जिससे मक्का, गन्ना आदि से इथेनॉल उत्पादन किया जा सके, इसमें केन्द्र सरकार मदद करेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में मक्के और दलहन की खेती को बढ़ावा देने की जरूरत है और इसके लिए राज्य के कृषि विभाग को पहल करनी चाहिए।

4 और जिला सहकारी बैंक खुले

श्री अमित शाह ने कहा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में कुल 6 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक हैं और निकट भविष्य में राज्य में 'पैक्स' के विस्तार को ध्यान में रखते हुए कम से कम 4 और जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की स्थापना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और जनजातीय लोगों के आर्थिक विकास के लिए व्होल ऑफ गवर्नमेंट एप्रोच के तहत राज्य सरकार के पशुपालन, कृषि, जनजातीय मामले और सहकारिता विभागों को मिलकर काम करना चाहिए।

कम्प्यूटराइजेशन पर दिया बल

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सभी 2058 'पैक्स' ने मॉडल बाय-लॉज को अपना लिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का उपयोग छत्तीसगढ़ में ड्राई एरिया ढूंढने के लिए करना चाहिए, जिससे सहकारिता के विस्तार में मदद मिलेगी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि कम्प्यूटराइजेशन होने के साथ ही हर 'पैक्स' को सीएससी बना देना चाहिए, जिससे 'पैक्स' द्वारा अनेक गतिविधियों का लाभ ग्रामीण जनता तक पहुंच सके।

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर प्रदेश में सर्वाधिक लाभ अर्जित करने वाला बैंक

- **जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर को 216 करोड़ का हुआ लाभ**
- **'सहकार से समृद्धि' की ओर बढ़ रहा है छत्तीसगढ़**

रायपुर। राज्य सरकार के नीतिगत फैसलों और केन्द्र सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ 'सहकार से समृद्धि' की ओर निरंतर आगे बढ़ रहा है। सहकारिता विभाग के आयुक्त श्री कुलदीप शर्मा ने बताया कि, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रायपुर प्रदेश में सर्वाधिक लाभ अर्जित करने वाला बैंक बन गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर को 216 करोड़ का सकल लाभ अर्जित हुआ है, जो कि विगत वर्ष से 84 करोड़ रूपए अधिक है।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रायपुर की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अपेक्षा व्यास ने कहा कि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में इस वर्ष का बेहतर लाभार्जन संभव हुआ है। उन्होंने बताया कि, बैंक से संबद्ध हितग्राहियों, किसानों तथा ग्राहकों की सुविधा बैंक के लिए सर्वोपरि है। यही कारण है कि अमानतदारों तथा किसानों के द्वारा बैंक के प्रति विश्वास जाहिर किया गया है।

किसानों को दिए जा रहे कई प्रकार के ऋण

बैंक से संबद्ध 550 सहकारी समितियों के माध्यम से अल्पकालीन कृषि ऋण के अतिरिक्त मध्यकालीन, दीर्घकालीन ऋण तथा ट्रेक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, तारफेर्सिंग आदि के लिए ऋण दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 में बैंक द्वारा 3.93 लाख किसानों को 1886 करोड़ का ब्याज मुक्त कृषि ऋण का वितरण किया गया।

विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना, व्हाइट रेवाल्यूशन 2.0 एवं 2 लाख नई सहकारी समितियों के गठन की समीक्षा

- **डेयरी, मत्स्य और बहुउद्देशीय पैक्स को सशक्त बनाने पर मंथन, अनाज भंडारण योजना की प्रगति की समीक्षा नवा रायपुर में हुआ**
- **डेयरी, सहकारिता मंत्रालय के सचिव ने कहा कि सहकारी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तथा व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 पूर्वी एवं मध्य भारत में समृद्धि के नए द्वार खोलेगा**
- **डेयरी, सहकारिता मंत्रालय के सचिव ने कहा कि सहकारी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तथा व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 पूर्वी एवं मध्य भारत में समृद्धि के नए द्वार खोलेगा**
- **सहकारिता मंत्रालय ने अगले पांच वर्षों में 75,000 नई डेयरी सहकारी समितियों के गठन के लक्ष्य की प्रगति की समीक्षा की**

रायपुर। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सहकार से समृद्धि के मंत्र के माध्यम से समृद्ध एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के विज़न तथा माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय आधुनिक अवसंरचना, प्रौद्योगिकी-सक्षम प्रणालियों एवं किसान-केंद्रित पहलों के माध्यम से देशभर में सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है।

इसी क्रम में रायपुर, छत्तीसगढ़ में 2 लाख नए एम-पैक्स, डेयरी एवं मत्स्य सहकारी समितियों का गठन एवं सुदृढ़ीकरण तथा सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना विषय पर एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ नाबार्ड, एफसीआई, नेफेड, एनसीसीएफ, एनडीडीबी एवं वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

बहुउद्देशीय ग्रामीण सेवा केंद्र बन रहीं पैक्स समितियां

विशेषज्ञों ने बताया कि, पैक्स समितियों को केवल ऋण वितरण तक सीमित न रखकर बहुउद्देशीय ग्रामीण सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके तहत खाद-बीज वितरण, धान खरीदी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, डेयरी, मत्स्य पालन, वेयरहाउसिंग और ग्रामीण उद्यमिता जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे किसानों और ग्रामीणों को गांव स्तर पर ही बेहतर सुविधाएं और रोजगार के अवसर मिलेंगे।

सचिव डॉ. भूटानी ने की अध्यक्षता

कार्यशाला को संबोधित करते हुए भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने कहा कि सहकारी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि डेयरी क्षेत्र ने गुजरात जैसे राज्यों में महिला सशक्तिकरण, पोषण सुरक्षा एवं आर्थिक समृद्धि में परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है। पूर्वी एवं मध्य भारत के राज्यों की अपार संभावनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जल संसाधनों, उपजाऊ भूमि एवं पशुधन की प्रचुरता इन क्षेत्रों में डेयरी क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए मजबूत आधार प्रदान करती है।

डॉ. भूटानी ने सभी सहभागी राज्यों से चुनौतियों पर खुलकर चर्चा करने, नवाचारपूर्ण विचार साझा करने तथा व्यावहारिक समाधान हेतु सामूहिक रूप से कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि केंद्र सरकार राज्यों को हरसंभव सहयोग प्रदान करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा आवश्यकता पड़ने पर उच्च स्तर पर समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा।

डेयरी सहकारी समितियों से जुड़ेगी महिलाएँ एवं गृहिणियां

कार्यशाला में इस बात पर भी विशेष रूप से प्रकाश डाला गया कि डेयरी सहकारी आंदोलन महिलाओं के नेतृत्व वाले ग्रामीण परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम बनकर उभर रहा है। डेयरी सहकारी समितियों से जुड़कर महिलाएँ गृहिणी की भूमिका से आगे बढ़ते हुए उद्यमी एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सक्रिय भागीदार बन रही हैं। इससे उन्हें संगठित बाजार, वित्तीय समावेशन, आजीविका के अवसर एवं निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भागीदारी प्राप्त हो रही है, जिससे जमीनी स्तर पर सहकारी वित्तीय इकोसिस्टम मजबूत हो रहा है।विचार-विमर्श के दौरान इस बात पर भी विशेष बल दिया गया कि इस सम्मेलन का एक प्रमुख उद्देश्य ÷सहकारिता में सहकार÷ की भावना को और अधिक सशक्त करना है, ताकि सहकारी आंदोलन के लाभ जैसे वित्तीय सेवाएँ, प्रौद्योगिकी, भंडारण अवसंरचना, डेयरी वैल्यू एडिशन एवं बाजार से जुड़ाव समाज के व्यापक वर्गों तक समावेशी एवं सतत तरीके से पहुँचाए जा सकें।

सहकारिता मंत्रालय ने व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 की प्रगति और अगले पांच वर्षों में 75,000 नई डेयरी सहकारी समितियों (DCS) के गठन एवं 46,000 मौजूदा समितियों के सुदृढ़ीकरण के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की प्रगति की समीक्षा की। डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी एवं सर्कुलरिटी पर बल देते हुए मंत्रालय ने कहा कि डेयरी पारिस्थितिकी तंत्र को केवल दूध उत्पादन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि बायोगैस, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, व्हे प्रोटीन एवं कार्बन क्रेडिट जैसे क्षेत्रों में भी विस्तार किया जाना चाहिए, ताकि किसानों एवं सहकारी संस्थाओं के लिए अतिरिक्त आय के अवसर सृजित किए जा सकें।

सहकारी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी एवं सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल्स के महत्व पर विशेष बल

सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी एवं सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल्स के महत्व पर विशेष बल देते हुए कहा कि वैश्विक ऊर्जा असंतुलन, ऊर्जा संकट, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान तथा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों से उत्पन्न आर्थिक अनिश्चितताओं के वर्तमान परिदृश्य में कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG), ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, बायो-एनर्जी उत्पादन, कार्बन क्रेडिट एवं गोबरधन आधारित मॉडल जैसे प्रयास ग्रामीण आजीविका को एक सतत एवं सशक्त भविष्य प्रदान कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि ये पहलें कृषि एवं डेयरी अपशिष्टों के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ आयातित ऊर्जा संसाधनों पर निर्भरता कम करेंगी, किसानों एवं सहकारी संस्थाओं के लिए अतिरिक्त आय के अवसर सृजित करेंगी तथा भारत में ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता एवं आत्मनिर्भरता की व्यवस्था को वैश्विक ऊर्जा संकट के इस दौर में और अधिक मजबूत करेंगी।

छत्तीसगढ़ शासन के सहकारिता विभाग के सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्ना ने कार्यशाला के आयोजन हेतु आभार व्यक्त करते हुए राज्य में सहकारी क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार डेयरी विकास, बायोगैस परियोजनाओं एवं अन्न भंडारण अवसंरचना को प्राथमिकता दे रही है।

नाबार्ड, एफसीआई, नेफेड, एनसीसीएफ एवं वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशनों के प्रतिनिधियों ने भी विचार-विमर्श में सक्रिय भागीदारी की।

स्वामी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित रायपुर द्वारा प्रकाशक एवं मुद्रक विवेकानंद झा द्वारा क्वालिटी आफसेट, पुरानी बस्ती, रायपुर से मुद्रित कराकर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित 16, पार्क स्ट्रीट-3, चौबे कालोनी रायपुर से प्रकाशित।
संपादक मंडल- विवेकानंद झा (प्रधान संपादक), विवेक पांडे (संपादक), फोन- 0771-4061702, 4031702, 4035702. वेबसाईट www.cgcoop.in E-mail: cgcoopnews@gmail.com